

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर
पत्रांक:सा0-3062 /मी0क्ष0/ 33 दिनांक, मीरजापुर, जनवरी, 21, 2021

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:-

Proposal of Renewal for diversion of 185.84 ha of Forest Land in favour of M/s Northern Coalfields Limited for Coal Mining in Kakri Open Cast Coal Mining in Sonbhadra District in the State of Uttar Pradesh (Online No. FP/UP/MIN/29061/2017) reg.

संदर्भ:-

1-भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग अलीगंज नई दिल्ली का पत्र संख्या- 8-350/1987-एफ0सी0(Vol) दिनांक- 01.09.2020

2- आपका पत्र संख्या- 477/11-सी- FP/UP/MIN/29061/2017 लखनऊ दिनांक- 02.09.2020

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक-01.09.2020 द्वारा 2020 द्वारा की गयी पृच्छाओं के संबंध में आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के आलोक में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट, ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या-2160/रेनुकूट/15-94 दिनांक 30.12.2020 (प्रति संलग्न) द्वारा बिन्दुवार सूचना/अभिलेख टेबुलर फार्म में निम्नानुसार संस्तुति सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया है।

क्र0 सं0	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग अलीगंज नई दिल्ली का पत्र संख्या- 8-350/1987-एफ0सी0(Vol) दिनांक- 01.09.2020 में अंकित विवरण	अनुपालन आख्या
1	2	3
i	The clear recommendation of CCF has not been provided in Part-III; as well as on the basis of improper recommendation of CCF the proposal has been recommended by Nodal Officer. Therefore, recommendation of the C.C.F. & Nodal Officer needs a review. They are required to submit clear recommendations and the recommendations shall be on agreeing renewal proposal or not in specific "Yes" or "No". Reasons for agreement/disagreement shall also be cited with the proposal;	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में लीज रेंट की देयता के सम्बन्ध में वन विभाग की ओर से माननीय उच्चमन्यायालय नई दिल्ली के समक्ष दाखिल विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या सिविल (सी) 22793/2013 व परिवर्तित अपील सिविल नम्बर 7614/2014 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य वना नाम नार्दन कोल्ड फील्डस लि० माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन है। माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के आलोक में नवीनीकरण हेतु संस्तुति की जाती है।
ii	DFO, Renukoot vide their letter no. 2869/रेनुकूट/15-38 dated 13.02.2019 had reported violation of section 2 of FCA, 1980 in this matter. The details about specific issues pertaining to contravention of section 2 of FCA, date of violation, extent of violation, officials responsible for violation, any other information relevant to this proposal shall be submitted;	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि रेनुकूट वन प्रभाग के पत्र संख्या- 2869/रेनुकूट/15-38 दिनांक- 13.02.2019 में उल्लिखित उल्लंघन का प्रकरण लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे० लीज भूमि से अलग भूमि का है जिसके संबंध में वस्तु स्थिति प्रभाग के अन्तिम पत्र संख्या- 3905/रेनुकूट/15-38 दिनांक- 18.05.2020 द्वारा स्पष्ट करते हुए रिपोर्ट उच्च स्तर पर प्रेषित की गयी है।
iii	The State Government has not submitted the complete compliance of the Ministry's earlier approval vide order no. 8-350/1987-FC dt. 30.05.1989;	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत अनुपालन आख्या सत्यापित करते हुए इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

iv	Site Inspection Report of the concerned CCF has not been submitted with the proposal which is mandatory as proposed renewal of lease is having extent >40 ha;	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रस्ताव के भाग-3 के साथ निरीक्षण टिप्पणी संलग्न किया गया है।
V	The NOC from other land owning agencies other than State Forest Department (if any) has not been submitted with the proposal;	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना में 185.84 हे० वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भूमि सम्मिलित नहीं है इस कारण अन्य एजेंसी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना अपेक्षित नहीं है।
Vi	The State Government has not clarified wheather the Environmental Clearance issued vide order dt. 11.05.2005 is valid for the instant proposal or not;	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा MOEF&CC पर ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या-IA/UP/CMIN/114168/2019 प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान में विचाराधीन है। पुष्टि हेतु अभिलेख संलग्न है।
vii	The State Government has not submitted the valid lease documents for the instant proposal;	<p>इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्व में पट्टाविलेख उपलब्ध कराया गया था जो कतिपय कारणों से अनुमोदित नहीं हो पाया। उ०प्र० शासन के आदेश संख्या-454/81-2-2020, पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक- 28 मई 2020 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण के समस्त प्रकरणों में Transfer of property Act 1882 के तहत संशोधित पट्टाविलेख उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्देश के क्रम में प्रभाग द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से एन०सी०एल० की ककरी परियोजना से संशोधित पट्टाविलेख उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया।</p> <p>उक्त अनुरोध के क्रम में महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्डस लि० ककरी परियोजना ने अपने पत्र संख्या- ककरी/महाप्रबन्धक/वन/2020/464 दिनांक- 12.08.2020 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के रिट याचिका संख्या- 33050/2010 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक- 14.07.2010 के आधार पर पट्टाविलेख के निष्पादन संबंधी कार्यवाही को स्थगित करने हेतु अनुरोध किया गया। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या- 33050/2010 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक- 14.07.2010 के संबंध में वस्तु स्थिति निम्नानुसार है :-</p> <p>“ जनपद-मीरजापुर, वर्तमान में सोनभद्र जिले में दुद्धीचुआँ एवं खड़िया कोयला परियोजनाओं हेतु 1305 हे० वन भूमि भारत सरकार के पत्र संख्या- 8-298/87-एफ०सी० दिनांक-30.07.1990 एवं इसके क्रम में विशेष सचिव, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या- एल 1319/14-3-929/87 वन अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक- 04.01.1991 द्वारा 40 वर्षों हेतु लीज पर दी गयी है। उक्त आदेश के अनुपालन में पट्टाविलेख</p>

की प्रति उच्च स्तर पर प्रेषित की गयी । पट्टाविलेख के निष्पादन के संबंध में उच्च स्तर से कुछ अभिलेखों की माँग की गयी जिसे उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के विभिन्न पत्रों द्वारा नार्दन कोल फील्डस लि० की दुद्धीचुआँ एवं खड़िया परियोजना से अनुरोध किया गया किन्तु एन०सी०एल० के स्तर से अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने पर कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट वन प्रभाग के पत्र संख्या-4021/रेनुकूट/15-39 दिनांक- 08.04.2010 द्वारा डम्पिंग कार्य पर रोक लगा दी गयी । प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट के उक्त पत्र दिनांक-08.04.2010 से क्षुब्ध होकर एन०सी०एल० द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष रिट याचिका संख्या-33050/2010 दाखिल किया गया । उक्त रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक- 14.07.2010 को स्थगन आदेश जारी किया गया है "।

उक्त आदेश केवल एन०सी०एल० की दुद्धीचुआँ एवं खड़िया परियोजना हेतु ही लागू है इसका उल्लेख करते हुए प्रभाग द्वारा एन०सी०एल० की ककरी परियोजना से संशोधित पट्टाविलेख उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया किन्तु एन०सी०एल० की ककरी परियोजना द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित उक्त अन्तरिम आदेश दिनांक-14.07.2010 ककरी परियोजना पर भी लागू होने का उल्लेख करते हुए संशोधित पट्टाविलेख उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है जो उ०प्र० शासन द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण के संबंध में जारी मूल आदेश दिनांक-28.12.1989 व वर्तमान में जारी संदर्भित आदेश दिनांक-28 मई 2020 का उल्लंघन है

Viii The state Government has not submitted details i.e. kml file with respect to the CA land where plantation has been carried out as per approval order no. 8-350/1987-FC dt. 30.05.1989;

इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित 185.84 हे० वन भूमि के बदले 189.84 हे० गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग हरदोई उत्तर प्रदेश में उपलब्ध करायी गयी है । उपलब्ध करायी गयी 189.84 हे० गैर वन भूमि को उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-3185/14-2-91/97/1991 दिनांक- 06.12.1991 द्वारा संरक्षित वन धोषित की जा चुकी है जिसकी पुष्टि हेतु प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग हरदोई का पत्र संख्या- 3975 दिनांक- 08.04.1994 की प्रति वन भूमि हस्तान्तरण से संबंधित नवीनीकरण प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या- 22 पर संलग्न है । उक्त गैर वन भूमि से संबंधित जी०ओ०रेफरेन्स मानचित्र टोपाश टि एवं के०एम०एल०फाइल की सी०डी० संलग्न है ।

ix	As per the DSS analysis report, the following shortfalls has been observed:	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित 185.84 हे० वन भूमि से संबंधित सशोधित जी०ओ०रेफरेन्स मानचित्र, टोपोशीट एवं के०एम०एल० फाईल की सी०डी० <u>संलग्न है</u> ।
a.	The calculated area of proposed diversion as per kml file submitted is found to be 183.91 ha whereas applied area for diversion in the renewal proposal is 185.84 ha;	
b.	As per Sol Map, some portion of Forest land applied for renewal is falling in the state of Madhya Pradesh;	
c.	A shift of Forest KML boundary applied for renewal has been observed w.r.t. location forest patch i.e. 185.84 Ha as shown in Sol Map;	
d.	Sol Map shows some Forest patches are not covered in the Forest land i.e. 185.84 ha applied for renewal.	

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत मामले में प्रेषित उपरोक्त बिन्दु की आख्या संस्तुति सहित एतद्सह संलग्नकर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय

(रमेश चन्द्र झा)

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या- 3062 अ/समदिनांक ।

प्रतिलिपि: प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट को उनके कार्यालय के संख्या-2318/ रेनुकूट /15-38 दिनांक 12.01.2021 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

(रमेश चन्द्र झा) 21/01

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

भाग-III

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

11	क्या वह स्थल जहाँ का वन क्षेत्र इसमें शामिल है का संबंधित वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है(हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और प्रेक्षण जो निरीक्षण रिपोर्ट में किए गए हैं को संलग्न करें ।	नहीं । (दिनांक 13.08.2019) को निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।
12	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक की सिफारिशों से सहमत है ।	हाँ ।
13	विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए संबंधित वन संरक्षक की विशेष सिफारिशें ।	प्रभाषी वन अधिकारी रेबुकट अंचल-2 में डालकीखेत संरक्षक के प्रस्ताव पर डालकीखेत अंचल कार्यालय हैदराबाद ।

इस कार्यालय के पत्रांक 2220/सीए/33 दिनांक 14-11-2019 के पत्रांक 15 में दिनांक 14 अक्टूबर 2019 के आदेश पर निरीक्षण की जाती है।

वन विभाग
बीरजापुर क्षेत्र
बीरजापुर

तारीख - 16.07.2019
स्थान - बीरजापुर

सहायक वन संरक्षक/प्रभाषी
अनपरा रेंज-
रेबुकट वन प्रभाग-सोनभद्र

हस्ताक्षर
नाम
सरकारी मोहर

निरीक्षण टिप्पणी

प्रस्ताव संख्या एफ.पी./यू.पी./माइन्स/29061/2017 पर जनपद सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत नार्दन कोल फील्ड्स लिमिटेड की ककरी परियोजना को लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे० वन भूमि के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में—

दिनांक 13.08.2019 को उप प्रभागीय वनाधिकारी पिपरी रेनुकूट वन प्रभाग एवं नार्दन कोल फील्ड्स लिमिटेड ककरी परियोजना के अधिकारियों के साथ प्रस्तावित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान प्रस्ताव में संलग्नक प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र में उल्लिखित 185.84 हे० वन भूमि को पुनः नवीनीकरण हेतु प्रस्तावित है । वह प्रस्तावित क्षेत्र की माँग न्यूनतम एवं अपरिहार्य पायी गयी है ।

(रमेश चन्द्र झा)

मुख्य वन संरक्षक

मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर